भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3459
जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

विद्युत वाहनों हेतु प्रोत्साहन और अवसंरचना

3459. श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में आंतरिक दहन इंजन वाले दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया (यात्री वाहन) वाहनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) मिश्रित व विद्युत वाहनों के विनिर्माण की त्वरित अंगीकरण योजना (एफएएमई) अर्थात् "फेम-इंडिया" स्कीम के अंतर्गत उक्त वाहनों के स्थान पर विद्युत वाहन लाने के लिए क्या रूपरेखा है;

(ग) इस पर भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (एसआईएएम) की क्या प्रतिक्रिया है और 'फेम-इंडिया' स्कीम के अंतर्गत ई-वाहनों के विनिर्माताओं और प्रयोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देशभर में सड़क-किनारे सार्वजनिक/निजी चार्जिंग स्टेशन (सौर और विद्युत) दोनों प्रकार के स्थापित करने के लिए रूपरेखा क्या है और की तारीख के अनुसार ऐसे कितने चार्जिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं;

(ङ) ई-वाहन चार्ज करने में कितना समय लगेगा और प्रति चार्जिंग की अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(च) देस में ई-वाहन के संचलन कार्बन फुट-प्रिंट में अनुमानतः कितनी कटौती होगी और तेल-आयात के कारण राजकोष पर पड़ने वाला भार कितना कम होगा?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): एसआईएएम से प्राप्त सूचना के अनुसार, सड़क पर चलने वाले लगभग 30 करोड़ वाहन आंतरिक दहन इंजन पर आधारित हैं।

भारी उद्योग विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के उद्देश्य से एक योजना नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है।

योजना के तहत, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से लगभग 10 लाख ई-दुपहियों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 7000 ई-बसों की सहायता किए जाने की योजना है। इस योजना में, सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले अथवा ई-तिपहिया, ई-चौपहिया और ई-बस सेगमेंट में वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर बल दिया जा रहा है। तथापि, निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-दुपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत, मांग प्रोत्साहन बसों के अलावा, जहां यह ₹20,000/किवा.घंटा है, सभी श्रेणी के वाहनों के लिए बैटरी की क्षमता अर्थात ₹10,000/किवा. घंटा से सम्बद्ध है।

सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स (सिआम) योजना का समर्थन कर रहा है।

(घ) और (ङ): इसके अलावा, योजना के तहत चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए ₹1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है और भारी उद्योग विभाग ने योजना के इस चरण में 1000 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए एक रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की।

फेम इंडिया योजना के चरण-I के तहत, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹43 करोड़ (लगभग) से लगभग 500 चार्जिंग स्टेशनों की सहायता की है। फेम इंडिया योजना के चरण-I के तहत स्वीकृत लगभग 500 चार्जिंग स्टेशनों में से लगभग 230 चार्जिंग स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने सूचित किया है कि उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 65 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए हैं और इसके अलावा ईईएसएल ने पहले ही देश में सरकारी कार्यालयों में लगभग 300 एसी और 170 डीसी कैप्टिव चार्जर लगाए हैं/लगाए जा रहे हैं।

ईईएसएल से प्राप्त सूचना के अनुसार, एक इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए अपेक्षित समय रेटिड क्षमता और चार्जर के प्रकार पर निर्भर करता है। विशिष्ट रूप से, डीसी -001 (15किवा.) चार्जर से 18 किवा.घंटा क्षमता की बैटरी वाली ई-कार के लिए चार्जिंग पूर्ण करने (0-100%) हेतु लगभग 70-80 मिनट लगते हैं। एनडीएमसी, दिल्ली से संचालित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए चार्जिंग की यूनिट लागत आईएनआर 9.5 प्रति यूनिट+जीएसटी है।

(च): फेम इंडिया योजना के चरण-I में मांग प्रोत्साहन के द्वारा लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की सहायता की गई है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हुई और लगभग 124 मिलियन कार्बन डाई-ऑक्साइ की कमी आई है।

*****